भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3105
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बढ़ती असमानता

3105. **श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी भारत के बीच बढ़ती असमानता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो आय असमानता को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय क्या हैं; और

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों में कुछ निगम समूहों के बीच संपत्ति का संकेंद्रण और भी खराब हो गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार भारत में आय असमानता में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गिरावट आई है और गिनी गुणांक 2022-23 के 0.266 और 0.314 से गिरकर क्रमशः 0.237 और 0.284 हो गया है। इस सुधार की प्रवृत्ति को विश्व बैंक के अनुमान (इंडिया पोवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, अप्रैल 2025) से और भी पुष्टि मिलती है, जिसके फलस्वरूप भारत का गिनी इंडेक्स 25.5 पर आ गया है (2011-12 के 28.8 की तुलना में), तथा आय समानता में भारत का स्थान विश्व स्तर पर चौथा आ गया है।

(ख) एवं (ग) सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य भारत की जनसंख्या के सभी वर्गों का विकास करना है। समावेशी विकास पर सरकार का ध्यान गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक

सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका विकल्प प्रदान करने और देश में समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "सबका साथ, सबका विकास" की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है।

इन उद्देश्यों के साथ, सरकार कई लक्षित कार्यक्रम लागू कर रही है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान के तहत निधि अंतरण, पीएम फसल बीमा योजना दावा भुगतान; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज सहायता; फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के लिए कृषि-अवसंरचना निधि। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री जन-धन योजना आदि सहित विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं।

भारत में एक प्रगतिशील प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था है, जिसमें उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न आय वर्ग के व्यक्ति की तुलना में उच्च दरों पर आयकर का भुगतान करता है। इसके अलावा, आयकर पर अधिभार एक निश्चित स्तर से ऊपर आय वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इस प्रकार उच्च आय वर्ग के करदाताओं के संबंध में एक मजबूत कराधान प्रणाली पहले से ही मौजूद है।

*****